HON. MEMBERS : Yes.

Amendment No. (1) was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added t othe Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

18.29 hrs.

DELHI MILK SCHEME*

श्री प्रेमचन्द वर्मा (हमीरपुर) : सभापति जी, 22-2-66 को दिल्ली मिल्क स्कीम के बारे में एक प्रश्न था कि क्या इसके मैनेजमेंट में बड़ी गड़बड़ है और दूध की जो कीमत है वह इस कारण से बढ़ रही है कि मैनेजमेंट में बहुत ही वेस्टेज है, दूसरे दिल्ली मिल्क स्कीम के मैनेजमेंट से वह लोग असन्तुष्ट हैं जिन लोगों से दूध लिया जाता है तो मंत्री महोदय ने केवल इतना कह कर जवाब दिया : नो सर, नो सर, डज नाट एराइज । इसका मतलब यह हुआ कि वह बिलकुल सन्तुष्ट हैं दिल्ली मिल्क स्कीम से कि वह बिलकुल ठीक ठाक चल रहा है । मेरा ख्याल इस के विरुद्ध और इससे अलग है क्योंकि मैंने उस को अच्छी तरह से देखा है। 1959 से ले कर आज तक की उसकी हालत को मैंने देखा है और पढ़ा है । वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि यह स्कीम जो 1959 में शुरू की गई थी उस का उद्देश्य यह था कि जो गांवों के लोग हैं नजदीक के उन लोगों को दूध की ठीक कीमत दी जाय और दूसरा उद्देश्य यह था कि दिल्ली के नागरिकों को सस्ते और मुनासिब दामों पर ठीक दूध सप्लाई किया जाय । लेकिन दस साल गुजर जाने के बाद भी वह दूध की सप्लाई बढ़ने के बजाय कम हो गई है और आज हजारों लोग ऐसे हैं, मंत्री महोदय को मालूम होगा, शायद पार्लियामेंट के मेम्बर भी उन को चिट्ठी लिखते रहते हैं कि लोग बीमार हैं, मर रहे हैं लेकिन उन को दूध मिलता नहीं है । हजारों लोग वेटिंग लिस्ट में हैं और दूध की हालत यह है कि गरीब लोगों को जो टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क मिलता था वह भी कैंसिल कर दिया है । अब गरीब लोगों के बच्चों को दूध नहीं मिलता है । उन्हें कितनी मुसीबत उठानी पड़ रही है लेकिन इन्होंने एक नादिरशाही आर्डर कर दिया और उसे कैंसिल कर दिया । कोई आलटरनेटिव अरेंजमेंट उन के लिए नहीं किया । यह इस दिल्ली के दूध की स्कीम की हालत है । आज दिल्ली की आबादी 1959 से लगभग दुगुनी से ज्यादा है । लेकिन दूध की सप्लाई जो है वह 1962-63 से कम हो गई है । एक चीज में कहना चाहता हूं मंत्री जी नाराज न हों, और हो भी जायें तो कोई बात नहीं । डेलही मिल्क स्कीम का नाम डेलही मिल्क स्कैंडल स्कीम होना चाहिए और इसका कारण मैं बताता हूं कि इस को डेलही मिल्क स्कैंडल स्कीम क्यों कहना चाहिए । जो यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन है इस दिल्ली मिल्क स्कीम का वह अपने गुनाहों पर परदा डालने के लिए विभिन्न बातें करता रहता है । कुछ लोगों को, बड़े लोगों को खुश करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के हथियार इस्तेमाल करता है । मैं केवल इतना इशारे में कह देना चाहता हूं और मैं मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले में मैंने जो शब्द कहे हैं कि विभिन्न तरीकों से जो मैनेजमेंट को चलाने वाले हैं वह बड़े आदमियों को खुश करने के लिए

*Half-An-Hour Discussion.

[श्री प्रेमचन्द वर्मा]

और अपना गोलमाल करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां करते हैं उन के ऊपर प्रतिबन्ध और रोक लगानी चाहिए और उन का इन्वेस्टीगेशन होना चाहिए।

मैं आपको एक पब्लिक एकाउंट्स कमेटी जो पहली लोक सभा की थी उस की 23वीं रिपोर्ट का पैरा पढ़ कर सुनाता हूं और फिर मैं मंत्री महोदय से सवाल करूंगा कि जनाब, आप ने भी इसे पढ़ा था और फिर कैसे मेरे सवाल का यह जवाब दिया था ? उस में वह कहते हैं :

Another item where there had been large increase was 'Miscellaneous expenditure' which had increased from Rs. 32,588 during 1.11.59 to 31.3.61 to Rs. 1,06,577 during 1961-62.

यानी यह 20 हजार रुपये जो मिसलेनियम एक्सपेंडीचर में था उस की रकम 1 लाख 6 हजार रुपये हो गई। मिसलेनियम एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि अन्धेर-खाता। जिसका कोई हिसाब नहीं है, जो कहीं एक्सपेंडीचर नहीं डाला जा सकता वह मिसलेनियस एक्सपेंडीचर में डाल दिया जाता है। 20 हजार रुपये से बढ़कर यह मिसलेनियस एक्सपेंडीचर 1 लाख 6 हजार रुपया हो गया। फिर आगे पब्लिक एकाउंट्स कमेटी कहती है :

"The Committee desire that the reason for the large increase in supervision and distribution charges and of miscellaneous expenditure should be re-examined and steps taken to reduce the various charges and to the extent possible in minimising the cost of production of the various products and also loss suffered by the scheme."

यह 1962 में रिपोर्ट मिली है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1962 से लेकर 1967 तक उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अब मैं इस स्कीम के बारे में आंकड़ों से साबित करना चाहूंगा कि यह स्कैंडल स्कीम क्यों है। यह इन्हीं के आंकड़े हैं, इसी सरकार के, इसी एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ हैं। मेरे पास उन के सब रिफरेंसेज मौजूद हैं। 1962-63, 1963-64 और 1964-65 इन तीन सालों का मैं बताता हूं। गवर्नमेंट कैपिटल 1962-63 में 164 लाख रुपये था, 1963-64 में 159 लाख था और 1964-65 में 187 लाख रुपये हो गया था। इन का टर्नओवर कितना रहा है वह अब मैं सदन के सामने रखता हूं। 288 लाख रुपये टर्न ओवर 1962-63 में था, 343 लाख 63-64 में रहा और 303 लाख 1964-65 में हो गया। टर्नओवर नीचे जा रहा है और फिर लास को देखिए 10 लाख 64 हजार रु० लास था 1962-63 में, 23 लाख 9 हजार रुपये 63-64 में और सभापति जी, आप हैरान हो जायेंगे उस कुर्सी पर बैठे हुये कि 97 लाख रुपया 1964-65 में लास है। यानी 1 हजार परसेंट लास बढ़ा है। 62-63 से 64-65 में 1 हजार परसेंट ज्यादा लास हुआ है। उस के बाद टर्नओवर पर लास जो है वह देखिए। 3·69 62-63 में था, 6·72 63-64 में और 32·26 64-65 में है। यह लास भी एक हजार परसेंट से ज्यादा है। 31 मार्च, 1965 तक 1 करोड़ 40 लाख रुपये का इस स्कीम में नुकसान हुआ है। यानी टोटल कैपिटल 187 लाख और नुकसान 140 लाख। कैपिटल का केवल 87 लाख बाकी रहा। यानी 75 परसेंट कैपिटल यह खा चुके हैं। तो इस से ज्यादा स्कैंडल इस से ज्यादा बेईमानी और इस से ज्यादा मिसमैनेजमेंट और क्या हो सकता है ?

अब मैं इस के बाद दूध की सेल की कीमत आप को बताता हूं। 1964 में दूध 62 पैसे किलो था। 1965 में 70 पैसे और 1967 में 104 पैसे किलो हो गया। इस तरह से उस की कीमत भी 75 परसेंट रेज कर दी है। इसके बाद घाटे का कारण में

आप को बताता हूं। यह घाटा कैसे बढ़ रहा है? एक बटर मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने खरीदा है। उस का इस्तेमाल 1962–63 में 12 परसेंट था, 63-64 में 5 परसेंट और 64-65 में 10 परसेंट हो गया था। उसी तरह आइस-क्रीम प्लान्ट है उसका इस्तेमाल साढ़े तीन परसेंट 62-63 में है और 63-64 में 4 परसेंट है। 1964-65 में वह सवा तीन परसेंट है। घी मैन्यूफैक्चरिंग प्लान्ट का यूज 48 परसेंट 1963-64 में और 20 परसेंट 1964-65 में हुआ है और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है उस का इस्तेमाल 1962-63 में 48 परसेंट है, 1963-64 में 52 परसेंट और 1964-65 में 50 परसेंट रहा है। लेकिन उस के बावजूद कहते हैं कि दस लाख रुपये के बोतल बनाने के दो मजीद प्लान्ट खरीदे हैं जब कि यह मशीन भी पूरा काम नहीं कर रही है। यह कितना अन्धेरखाता है इसमें? दस लाख रुपये की मशीन बोतल बनाने के लिए खरीद ली। 4 लाख 62 हजार की मशीन 1961-62 में खरीदी थी। वह 1965 तक इस्तेमाल नहीं हुई और फिर आटोमेटिक मशीन इम्पोर्ट की गई, फारेन एक्सचेंज उस में खर्च किया गया। उस मशीन के लिए 1964 में टेकनिकल ऐडवाइजर ने कहा कि यह काम करने काबिल नहीं है और आज वह लोहे की सूरत में यहां पड़ी हुई है।

इसके बाद बोतलों की ब्रेकेज है। मिनिस्टर साहब जवाब देंगे कि हमारा परसेंटेज बहुत कम है दुनिया से या बम्बई कलकत्ते से मुकाबिला वह करेंगे। लेकिन 31-3-63 तक ब्रेकेज इन की जो है वह है 847237 और 1964-65 में यह है 529754। सभापति जी, आप अन्दाजा लगाइए, 2 हजार रुपये रोज की इनकी बोतलें टूटती हैं। लेकिन यह बात ऐसी है, यह कह सकते हैं कि 2 हजार रुपये रोज की बोतलें टूटती हैं, मगर यह ऐसा है नहीं वह सारी की सारी बोगस एन्ट्री होती है। इस की जांच होनी चाहिए। कोई भी कारोबार हो अगर उस के अन्दर इस तरह बोतलें टूटें तो दूसरे दिन उसका दिवाला निकल जायेगा।

बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बोगस एन्ट्री होती है। इस्तेमाल थोड़ा होता है, दिखाया ज्यादा जाता है और बाकी चोरी में बेच लिया जाता है। इसके बाद साढ़े आठ सौ किलो घी 7 जनवरी, 1966 में गड़बड़ हो गया। एन्ट्री नहीं हुई और उसका आज तक कोई पता नहीं। उसके बाद 6750 पैकेट मक्खन के एक रोज में गबन हो गये। 9384 आइस क्रीम के बार एक दिन में गुम हैं। यह तो एक दिन की बात है, न जाने रोज कितनी चोरियां होती होंगी? दिसम्बर 1963 में 954 टिन गुम हो गये। आज तक पता नहीं लगा है। लेकिन सारा मामला हश-अप कर दिया जाता है। फिफटी-फिफटी करके मामला साफ कर दिया जाता है। इन बातों को दोनों मिनिस्टर, श्री जगजीवन राम जी और श्री शिन्डे साहब की नोटिस में लाया हूं। पार्लयामट का मेम्बर होने के नाते मेरा फर्ज है कि ऐसी बातों को आपके सामने रखूं और आप इन तमाम फैक्ट्स को देखकर इस पर कार्य वाही करें।

सभापति महोदय : बहुत टाइम हो गया है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूं, कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आप टाइम बढ़ा दीजिए।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं अब समाप्त कर रहा हूं।

यह फैक्ट्स सामने आ जायेंगे तो जनता की सेवा होगी। मैं जानता हूं कि ट्रान्सपोर्ट के अन्दर लाखों रुपये की गड़बड़ है। बसेज के अन्दर फर्जी पुरजे डाले जाते हैं और नये पुरजे की कीमत वसूल की जाती है। पांच आदमियों की जहां जरूरत है वहां पर बीस आदमी रखे जा रहे हैं, वे हाजिर नहीं होते हैं, 50 परसेंट से ज्यादा हाजिरी नहीं होती है। दूध के कन्ट्रैक्ट ज्यादा लिखवाये जाते हैं। और बेचते कम हैं। फरजी एडवांस दिए जाते हैं। किताबों में कितने ही एडवान्सेज हैं जोकि बट्टे खाते में डाल रखे हैं। इसमें भी फिफटी-फिफटी परसेन्ट कर रखा है।

[श्री प्रेमचन्द वर्मा]

अब मैं कुछ सजेशन्स देना चाहता हूं ; पहला सजेशन्स तो यह है कि इस दिल्ली मिल्क स्कीम की रेगुलर बलेन्स शीट बनाई जाए। आज इसका कोई हिसाब किताब नहीं है । 6 महीने की मेहनत के बाद भी इसका हिसाब किताब नहीं मिल सकता है । इसलिए इसको बलेन्स शीट अलग बनानी चाहिए । जसे कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज में होता है। इसके अलावा जो चोरियां और बेइमानियां होती हैं उनको रोकने के लिये एम्मी-डिएटली एक कमेटी बनानी चाहिए चाहे पार्लमेंट के मेम्बरों को पार्लमेन्ट्री कमेटी बनाई जाए या फिर इसको पब्लिक एकाउंट्स कमटी के सुपुर्द कर दें या पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज कमेटी के सुपुर्द कर दें। बहरहाल इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तौर से होना चाहिए ।

इसके अलावा मैं एक अर्ज और करना चाहता हूं कि सारी कारगुजारी इस वक्त तक तो जो हुई है उसका सारा केस पुलिस को देना चाहिए। जितने बेईमानी, चोरी और गड़बड़ी के केसेज हैं उन को आप सी०बी०आई० के सुपुर्द करें और देखें कि क्या हो रहा है । मेरा यह अन्दाजा कि अगर इन गड़बड़ियों को बन्द कर दिया जाए तो जो दूध आज 1.04 बिक रहा है वह 75 पैसे में बिक सकेगा और टोन्ड मिल्क के दाम भी कम किये जा सकेंगे । दूध को शार्टेज जान-बूझ कर बना रखी है ताकि ब्लैक-मार्केटिंग हो सके ।

मैं अब यहां पर लेबर वगैरह की बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन तमाम सबूत मिल चुके ह, मेरे पास तहरीरी सबूत भी हैं, मिनिस्टर साहब चाहेंगे तो उनको बता दूंगा । मेरे पास तमाम के तमाम सबूत हैं । सारा का सारा जो जनता का रुपया है, तीन करोड़ रुपया उसे ये खा गये लेकिन फिर भी गरीब आदमी के लिए कोई दूध नहीं है । और बड़े आदमियों को कोई तकलीफ नहीं है । दूध अफसरों के घरों पर ही पहुंच जाता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका पूरी तौर से इन्वेस्टिगेशन करायें, पूरी तहकीकात करायें और दिल्ली मिल्क स्कीम के बजाये इसका नाम दिल्ली मिल्क स्कैंडल स्कीम कर दें ।

MR. CHAIRMAN : There are only four names balloted. I am not going to relax the rule this time. Only the four gentlemen whose names have been balloted will be allowed to ask questions. That is all. We exceed our limit every day and the staff keeps sitting overtime.

श्री रणजीतसिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, हमारी खुशकिस्मती है कि फूड मिनिस्टर साहब खुद हाजिर हैं । इनकी नोटिस में जो मसले लाये गये हैं, यह सही है कि यह बड़ी तशवीश की बात है । मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा ताकि अवाम को दूध सस्ता मिले, खालिस दूध मिले, सस्ता और खालिस घी मिले, सस्ता और खालिस क्रीम और बटर मिले, क्या इसके लिए कोई स्कीम उनके जेरे गौर है ? दिल्ली के अलावा जो और बड़े शहर हैं उनके लिए भी क्या कोई मास्टर-प्लान उनके जेरे गौर है कि ऐसे इलाकों में जैसे वेस्टर्न यू० पी० और हरयाना, वहां पर अच्छी नस्ल की भैंसों और गायों के लिए घोसियों को या जो नान-किसान मवेशी पालने के काम करते हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज दी जायें ? इस किस्म का कोई फेज्ड प्रोग्राम है कि क्रेडिट फैसिलिटीज देकर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में दूध दस्तियाब किया जाए दिल्ली के अलावा, कलकत्ता, बम्बई या दूसरे जो बड़े शहर हैं उनके लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम है ?

दूसरी बात यह है कि जिस किस्म की शिकायतें आई हैं और वह अगर सही हैं तो उनकी छान-बीन या तो पार्लियामेंट के मेम्बरों पर छोड़ दो जाय या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट बाई सर्टेन असेसर्स यानी मैजिस्टोरियल इन्क्वायरी करवायेंगे ताकि जितनी बातें कही गई हैं, खालिस दूध न मिलने के बारे में या और जो ग्लैरिंग चार्जेज है, वह अनअर्थ हो सकें और पब्लिक कान्फीडेन्स

बहाल हो सके ? इस किस्म की कोई कमेटी बनाने की तजवीज पर गौर फरमायेंगे ?

MR. CHAIRMAN : Shri Rabi Ray... He is not here. Shri Kundu may ask a question in his place.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Some time ago when a discussion started, in the form of a supplementary I posed certain problems. My object in participating in today's debate is that we must put our heads together to see that the Delhi Milk Scheme improves its present catering service to the people. I just want to touch one or two points and ask a question.

The hon. Minister said once that on the waiting list there are about 54,000 people.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : 60,000.

SHRI S. KUNDU : He said on 15-2-1968 that there were 54,424 people and then on 22-2-1968 he said that there were 50,000 people on the waiting list. I do not know which is true. He ought to clarify this.

Then, I made one allegation that there were thousands of spurious cards in Delhi and actually there is no shortage. There is an artificial shortage. My specific question is this. What is he going to do to check the circulation of spurious cards entered in the name of different people ? The simple thing to check it would be....

MR. CHAIRMAN : Please ask a direct question.

SHRI S. KUNDU : In an arbitary way milk bottles are being given through chits, which is not accounted for, to some people. I have got here several documents to prove that. 400 bottles were given to a gentleman in the course of three days. Then there are also chits which are issued at the discretion of the officers saying 'issue 20 bottles, issue 40 bottles' and so on, and if the Depot Managers do not give, then they are taken away from their jobs.

Another point that I want to touch here is about the 2,000 young men and women who are working here. It is a very good thing that part-time job is provided to poor people; they get Rs. 25 or Rs. 50. But there is no security of service. Anybody who wants to turn them out can just turn them out....

MR. CHAIRMAN : He should put his question only.

SHRI S. KUNDU : I am putting the question. I appeal to the Minister to be sympathetic to them. I have already told him. Let him consider the question of these young men and women and find out a solution; if the boys are really wrong, he can haul them up, but if they are not, he should protect them.

I just want to quote a few lines from the *Times of India*, about a girl who wanted to....

MR. CHAIRMAN : I will not allow it. We cannot afford to sit here for a full debate. He should just ask his question. That is all.

SHRI S. KUNDU : I will just quote this. It was that a girl complained...

MR. CHAIRMAN : No, no. He will just ask his question.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : What is the allegation.

SHRI S. KUNDU : The allegation is that she wanted to deposit the money, but she was not allowed; nobody came to collect it and she was locked up in the booth; then she felephoned to the Chairman and then somebody came to her rescue. There are specific cases of harassment which the hon. Minister should look into and steps should be taken to see that the efficiency is improved. Let them tell us how best the efficiency could be improved.

One of my suggestions is this. There are various types of milk—toned, double-toned and all that. My suggestion is that they should have one uni-

[Shri S. Kundu]

form category of this milk or at the most two varieties of this.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि यह जो दिल्ली मिल्क स्कीम है वह अपने पैरों पर खड़ी हो और दिल्ली के लोगों को शुद्ध दूध सप्लाई कर सके। इसकी दृष्टि से सरकार को एक लांग रेंज पालिसी बनानी चाहिये और इसके लिये प्रबन्ध करना चाहिये, यह बात ठीक है। लेकिन मैं इस का समर्थन करता हूं कि जो डिपो मैनेजर्स खुली बोतलें बेचते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी शिकायतें उन की आती हैं और किसी की नहीं आती हैं।

दूसरी बात यह है कि जहां दूध प्रोक्योर होता है वहां पर करप्शन होता है। इस दूध के करप्शन को रोका जाये। क्या मंत्री महोदय इस पर कोई लांग रेंज पालिसी बनायेंगे जिससे दिल्ली के सब लोगों को दूध मिल सके।

दूसरी बात यह कि प्रोक्योरमेंट की गारेन्टी रहे क्योंकि सब से ज्यादा गड़बड़ प्रोक्योरमेंट में होती है। इस के लिये क्या सरकार कोई कैट्ल फार्म बनाने की बात पर विचार करेगी जैसे कि बम्बई में है ?

तीसरी बात यह कि बेबी फूड बनाने की जो फैक्ट्री है दिल्ली के आस पास उन में काफी दूध खर्च होता है। वह आगे एक्सटेंड न हों क्या इस तरह का कोई प्रतिबन्ध सरकार लगायेगी ?

चौथी बात यह जो टोन्ड मिल्क है उस के सम्बन्ध में जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो कि बहुत गरीब तबका है, उन को प्रिफरेंस दिया जायेगा ? स्लम में रहने वालों को टोन्ड मिल्क मिलेगा क्या इस की कोई गारन्टी सरकार देगी ? साथ ही इस को अगर सब्सिडाइज करने की जरूरत पड़े तो इसको सब्सिडाइज भी होना चाहिये।

पांचवीं चीज यह कि यहां का जो कारपोरेशन है उस को इस दूध की क्वालिटी के बारे में सैम्पल लेने की इजाजत नहीं है। जब कभी इसका सैम्पल लिया गया तो कई बार देखा गया कि मिल्क की क्वालिटी ठीक नहीं थी। अगर आप की मंशा लोगों को शुद्ध दूध देने की है तो आप को कारपोरेशन को परमिट करना चाहिये कि वह जब चाहें आप के दूध का सैम्पल लें, और अगर उस में कोई गलती साबित हो तो उस की एन्क्वायरी की जाय और जो कन्सर्न्ड आदमी हों उन को सजा दी जाये।

छठवीं बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक कमेटी पार्लियामेंट के मेम्बर्स की बने जो कि यह सोचे कि किस तरह से दूध के प्रोक्योरमेंट को सप्लिमेंट किया जा सकता है, और किस ढंग से जो गड़बड़ियां हैं उन को ठीक किया जा सकता है।

श्री बलराज मधोक : सभापति महोदय, मैं श्री प्रेम चन्द वर्मा को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने ज्यादा तथ्य इस स्कीम के बारे में हाउस के सामने पेश किये।

जो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं उस में पहली बात तो यह कि इन तथ्यों के प्रकाश में क्या वे कोई पार्लियामेंट्री कमेटी या कोई दूसरी कमेटी नियुक्त करेंगे जो कि इन सारी बातों की जांच करे ? साथ ही अगर यह बातें ठीक हैं, जैसी कि मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक हैं, तो फिर जो लोग दोषी हों उन्हें दण्ड देने की व्यवस्था हो।

दूसरी बात यह कि एक तरफ तो हजारों आदमी वेटिंग लिस्ट पर हैं और दूध है नहीं—प्रोक्योरमेंट के लिये जब आप ने कोशिश की तो वह मिलता नहीं,—तब जैसा सुझाव दिया गया है क्या आप दिल्ली के अन्दर या उसके इर्द-गिर्द कोई कैट्ल फार्म कायम करेंगे या कुछ छोटे घोसियों को कर्जा देकर गाय और बैल पालने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि सारा दूध इस स्कीम को मिले और जो आप की प्रोक्योरमेंट प्राब्लम है वह हल हो ?

तीसरी बात जो है वह यह कि यह एक सरकारी इदारा है इसलिये नुकसान हो

रहा है, और जो भी नुकसान होगा वह जनता का होगा, टैक्स-पेयर का होगा । जो हालत आप की दूसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्स की है वही इसकी भी है, तब क्या आप इस बात पर विचार करेंगे इस अंडरटेकिंग का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह इस ढंग से बदला जाय कि इस में कुछ प्राइवेट व्यवसाय के लोग आयें और पब्लिक कम्पनी के रूप में इस को चलाया जाय ताकि उन को इस के घाटे और नफे का खयाल हो । जिस तरह से दिल्ली की आबादी बढ़ रही है उस में उस के लिये एक डेरी पर्याप्त नहीं हो सकती । इन हालात में आप चाहे प्राइवेट सैक्टर कहिये या कारपोरेट सैक्टर कहिये, एक बड़ी डेरी चाहिये । आप एक साल में तीन या चार न तो कम से कम एक बड़ी डेरी बनाने की योजना बनायें ताकि दिल्ली की जनता को दूध मिल सके ।

मेरे यह चार स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, जिनका मैं उत्तर चाहूंगा ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I welcome this opportunity to discuss the problems of the Delhi Milk Scheme. I can submit at the outset that there can always be some scope for improving the efficiency and the work of an undertaking like the Delhi Milk Scheme. But may I submit that Mr. Prem Chand Varma, who is a very valued colleague of ours, has been very unfair to the Delhi Milk Scheme and its working; though, otherwise, he is a very responsible member, today I have seen him making irresponsible statements. I say this with a sad heart....

श्री प्रेम चन्द वर्मा : या तो उन से इन्कार कीजिे, वर्ना आपकी जो किताबें हैं उन को जला दीजिये । मैं भी उतनी ही इज्जजत रखता हूं जितनी आप रखते हैं आप को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें । या आप मेरी बातों को झूठा बतलायें ।

SHRI BAL RAJ MADHOK: You deny the fact. You cannot just say this. If you can prove that they are wrong, then we can understand.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Why is he not patient?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम :) किसी को इस तरह आसानी से `ईमानी या दूसरी चीजें नहीं कहनी चाहिये ।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : क्या किसी को इररिस्पांसिबल कहना पालियामेंट्री है ?

श्री जगजीवन राम : बिल्कुल पालियामेंट्री है ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I have said, and I will repeat what I have said. I said, he is a responsible member, but he has today made irresponsible statements.

MR. CHAIRMAN : There is nothing unparliamentary in the use of the word 'irresponsible'.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The first point that has been made out is that the Delhi Milk Scheme is not in a position to meet the full requirements of the Delhi population. It is true that the milk which the DMS procures and distributes does not cover the total requirements of the Delhi population. But may I humbly ask whether there is any scheme in the country anywhere which meets the requirements of the entire population of any city? Take the case of Calcutta. The Calcutta population is almost double that of Delhi, but they are not in a position to distribute even that much quantity which the DMS is in a position to distribute to the Delhi population. The same can be said to be true about Bombay and other cities also.

19 hrs.

SHRI BAL RAJ MADHOK : But there is a difference. In Delhi almost all the private dairies have been abolished and the DMS has been given a sort of monopoly. If they had been allowed, this problem would not have arisen. So, let him not compare the position here with that in the other cities. It is no argument that

[Shri Bal Raj Madhok]

because the people of other places are suffering we should also suffer.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: It is not a fact. No monopoly has been given to the DMS. Other private dairies are also operating.

SHRI JAGJIWAN RAM: Shri Kanwar Lal Gupta had in fact suggested that.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: In fact, Shri Kanwar Lal Gupta had mentioned that. In fact, he had suggested that other private milk product manufacturers and dairies should be banned so that the DMS would be in a position to augment its resources. I think therein he was right. But may I submit that though we may endeavour to augment the milk procurement and supplies for the DMS I do not think that in the immediate future we shall be in a position to meet the full requirements? After all, the coverage of the requirements of the entire population will depend upon the extent to which DMS is in a position to procure milk. As at present, DMS is not in a position to procure the milk required, though milk procurement has been going up from year to year. It is not a fact as alleged by Shri Prem Chand Verma that milk procurement has been going down. In fact, as compared to the last few years, the procurement of milk has been going up steadily.

For instance, take the month of February. In the month of February, 1961 during the year 1960-61, the monthly procurement was only 21 lakh litres. I am giving only the broad figures and I am not going into the details. But during last month, the procurement has been 55 lakh litres, which is almost 2½ times more than what was procured in 1960-61. Even as compared to 1965-66, in the month of February this year, the procurement has been more. In 1965-66 it was only 48 lakh litres, but it has risen to 55 lakh litres.

SHRI S. KUNDU: It leaks out through spurious cards.

SHRI JAGJIWAN RAM: They are also respectable people.

SHRI S. KUNDU: That was what I said, but then the Congressmen jumped up.

SHRI RANDHIR SINGH: The Opposition is also there.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: We are trying to make efforts to see that procurement goes up and to the extent possible we are able to increase the milk supply to the Delhi population.

Some statements have been made to the effect that the expenditure of DMS is very high. That is also not a correct statement of facts. In 1965-66 an expert committee headed by very eminent experts in the dairy world, who are known not only in India but all over the world went into the working of the DMS. They went into a number of other problems of the DMS but they went particularly into the administrative working and the administrative costs incurred by the DMS and they suggested some norms. Based on the experience elsewhere of other dairies in the country they suggested that the normal expenditure for procurement, distribution and processing should not exceed 21 paise a litre, because elsewhere similar dairies are incurring expenditure only of that order. Actually in 1965-66 the DMS expenditure in this regard was only 19.75 paise a litre, which was even below the norm prescribed by the expert committee. In fact, there has been considerable increase in the cost and expenditure of the DMS during the last two years, because the salaries, wages, dearness allowance etc. has gone up, and even the purchase price of the milk procured has gone up, but even then in 1966-67 the expenditure per litre was only 20.4 paise.

SHRI BAL RAJ MADHOK: How does he explain the loss?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: During the current year, it works out to about 20 paise a litre. Even during the last year, the DMS operated below

21 paise, the norm prescribed by the expert committee. This includes breakage of bottles, administrative costs, salaries, processing costs and procurement costs.

As the House is aware, we are procuring milk from long distances, and so we have to cover the transport expenditure and other expenditure also.

SHRI BAL RAJ MADHOK : How does he explain the loss of more than Rs. 1 crore ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I am coming to that.

I have already submitted that our efforts should be always to see that the working is improved, that efficiency is improved and that costs are minimised. But at the same time, it is not correct to say that everything is wrong and there is inefficiency in the DMS and so on, because that would be unfair to undertaking itself.

It is a factual statement that the DMS has been incurring heavy losses. But the reason is that we are providing the Delhi population with the cheapest milk in the country. No other dairy in the country, except one or two, is in a position to supply milk at the price at which the DMS is supplying. For instance, in Bombay, milk is supplied at the price of Rs. 1.70 per litre, while in Delhi we are supplying milk at the price of Rs. 1.04 a litre. Even then, toned milk is supplied at the price of 74 p. per litre, and double toned milk is supplied at 54 p. per litre, as compared to much higher prices elsewhere in Calcutta and other cities. At the same time the DMS is required to procure milk at a much higher price. For, the cattle-owners have also got their problems, and they must get also a remunerative price. Unless they get a remunerative price, the production of milk will not increase, and so we have to see that the interest of the cattle-owners is also adequately protected. So, while the procurement price is going up, the price at which we are supplying milk to the Delhi population is much lower compared to that in many other milk schemes. So, there is a gap, which is very wide, and this is mainly due to the fact that we are required to pay a higher price for procurement and we supply the milk to the Delhi population at a lower price. This is the main reason for the loss.

Here, may I ask one question of Shri Bal Raj Madhok in all fairness ? If they feel that the scheme is going in the wrong way, why should the DMS not be taken over by the Delhi Administration ?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Let them first make good the deficit of the last five years.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : We make this offer to the Delhi Administration. If they think that something is being wrongly managed, why should they not be fair enough to take this over and run it ? Why are they not prepared to accept this fair offer ?

SHRI BAL RAJ MADHOK : It is not a fair offer. They have made a mess of it. There are so many losses and still the hon. Minister wants the Delhi Administration to take it over. Let them clean up the mess and then we shall take it over. Let them first make good the deficit.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : A suggestion has been made why a committee of Members of Parliament should not be set up. What is there to be enquired into when the administrative costs have been found to be below ever the norms suggested by the expert committee ? The procurement price is not within our control and we have to look to the market price at which milk is being sold to the private dairy-owners, and the competition that we have to face in the procurement of milk in the open market. Since a committee of experts has recently gone into this matter, what is there to be enquired into ? May I however inform the House that Government are considering a proposal that the DMS should be con-

[Shri Annasahib Shinde]

verted into a commercial organisation? I welcome Shri Bal Raj Madhok's suggestion in that direction, and that suggestion deserves consideration and Government are actually considering that suggestion.

श्री इसहाक सम्भली : क्या यह सही नहीं है कि जो दिल्ली मिल्क स्कीम ऐडवाइजरी कमेटी बनी हुई है इसमें कुछ एम०पीज० भी है उन्होंने इसके ऐडमिनिस्ट्रेशन को बहुत एक्सपेंसिव बताया है और यह कहा है कि दूध की कीमत न बढ़ाई जाय लेकिन उस कमेटी को कोई अधिकार नहीं है, उस को सिर्फ ऐडवाइज करने का हक है तो क्या उस को अधिकार देंगे और जो कमेटी बनी हुई है उस की सिफारिशों को मानने के लिये तैयार हैं, और उस के मेम्बरों की बात को मानेंगे ....

[شری اسحاق سمبھلی—کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جو دھلی ملک سکیم ایڈوائزری کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں کچھ ایم. پیز. بھی ہیں انھوں نے اس کے ایڈمنسٹریشن کو بہت ایکسپینسو بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ دودھ کی قیمت نہ بڑھائی جائے لیکن اس کمیٹی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے اس کو صرف ایڈوائز کرنے کا حق ہے تو کیا اس کو ادھیکار دینگے اور جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کی سفارشوں کو ماننے کے لئے تیار ہیں اور اس کے میمبروں کی بات کو مانیں گے . . .

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I am not yielding.

श्री जगजीवन राम : मेम्बर तो कह देंगे कि मुफ्त में ही दूध दे दो तो कैसे मान लेंगे ?

श्री इसहाक सम्भली : ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिये जो सुझाव दिया है उसको मानने के लिये तैयार हैं ?

[شری اسحاق سمبھلی—ایڈمنسٹریشن کو سدھارنے کے لئے جو سجھاؤ دیا ہے اس کو ماننے کے لئے تیار ہیں -]

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Shri Kundu made the point that there are a large number of spurious card-holders. I admit that there is a substantial number of them. But we are trying to set up a detection squad; we are trying to tally them with ration cards.

SHRI JAGJIWAN RAM : Many ration cards themselves are spurious !

SHRI ANNASAHIB SHINDE : There are certain limitations. But I welcome his suggestion. It will be our endeavour to see that special efforts are made to detect spurious cards.

SHRI S. KUNDU : If he accepts my suggestions, it will stop in three days.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Then he said we are not sympathetic to the depot managers who are working there, the students. May I tell him that only because we have sympathy for the students who come of very poor families that we have given them this part-time employment. It was because we were motivated by this consideration that they should get some income. Where is the question of giving security of service ?

SHRI S. KUNDU : But you take away their jobs arbitrarily. Some of your officers misbehave towards them. I can cite instances.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : We have not terminated the service of any depot manager except in the case of those who have indulged in some malpractices, changing of seals, tampering with milk etc. Otherwise, we are very sympathetic to them. May

I assure the House that we shall continue to be sympathetic towards them and consider their problems. I shall be prepared to discuss this with the hon. Member if there are any problems.

The usual problem of a cattle colony has been raised. What is the experience of Bombay in having such a colony? In Bombay, the cattle colony is being maintained in Aarey. The cost of production per litre comes to Rs. 1.60. The justification for maintaining a cattle colony can be there only if we are in a position to supply milk to the consumers at a reasonable price. Who will purchase the milk if the cost of production itself is Rs. 1.60 or Rs. 1.80 ? At least a large section of our population is so poor that it is very difficult for them to purchase milk at such a very high price.

SHRI BAL RAJ MADHOK : What about private *ghosi* colonies ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Shri Kanwar Lal Gupta and Shri Kundu talked of providing milk to the poorer sections of the society. Double toned milk is being supplied to persons whose income is less than Rs. 300 per month. We have been very sympathetic to the lower categories and the Delhi Milk Scheme will continue to follow that policy.

19.14 Hrs.

The lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, March 26, 1968/Chaitra 6, 1890 (Saka).